+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

TODAY'S ANALYSIS
(आज का विश्लेषण)
(06 January 2025)

Sources:

The Hindu, The Indian Express, The Economics Times & PIB

Important News:

- भारत और ईरान की चाबहार बंदरगाह के विकास और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने पर चर्चा
- भारत में गरीबी अनुमान ऐतिहासिक रूप से पांच प्रतिशत से नीचे पहुंचा
- जॉर्ज सोरोस को दिया गया अमेरिका का 'प्रेसिडेंशियल मेडल' क्या है?
- MCQ

भारत और ईरान की चाबहार बंदरगाह के विकास और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने पर चर्चा:

चर्चा में क्यों है?

- भारत और ईरान ने 3 जनवरी को चाबहार बंदरगाह के संयुक्त विकास, व्यापार और आर्थिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के तरीकों और कृषि और कुछ अन्य क्षेत्रों में संभावित सहयोग सहित अपने संबंधों की व्यापक समीक्षा की।
- चाबहार बंदरगाह के विकास ने भारत और ईरान के लिए व्यापार और आर्थिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किए हैं। यह बंदरगाह तेहरान के विरुद्ध अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे से बाहर है।
- वार्ता में ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उप विदेश मंत्री माजिद तख्त रवांची ने किया, जबकि भारतीय पक्ष का नेतृत्व विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने किया।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

भारत और ईरान के मध्य चर्चा के प्रमुख बिंदु:

- विदेश मंत्रालय (MEA) ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों ने "चाबहार बंदरगाह, कृषि सहयोग, व्यापार और आर्थिक मुद्दों के साथ-साथ सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के संबंधों सहित द्विपक्षीय संबंधों के पूरे स्पेक्ट्रम की समीक्षा की"।
- ईरानी उप विदेश मंत्री ने लोगों से लोगों के बीच आपसी संबंधों को बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया।
- इस चर्चा में अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया और दक्षिण काकेशस की स्थिति सहित वर्तमान क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों को भी शामिल किया गया। विदेश सचिव ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास में सहायता के लिए चाबहार बंदरगाह के महत्व पर प्रकाश डाला।
- दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स और SCO सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
- एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने कहा कि ईरान भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति फिर से शुरू करने के तरीकों पर विचार कर रहा है और चाबहार बंदरगाह के माध्यम से पेट्रो-रसायन क्षेत्र सहित समग्र व्यापार टोकरी का विस्तार करने का इच्छुक है।

VAJIRAO & REDDY INSTITUTE
India's Top Potential Training Institute for IAS
+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

भारत ने अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद 2019 के मध्य में ईरान से कच्चे तेल की खरीद बंद कर दी थी।

चाबहार बंदरगाह की अवस्थिति:

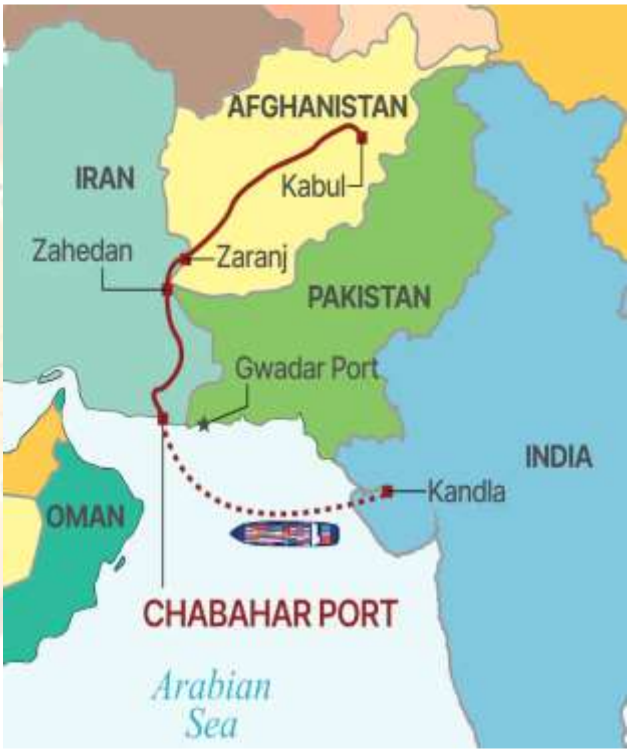

- ऊर्जा-समृद्ध ईरान के दक्षिणी तट पर सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में स्थित चाबहार बंदरगाह का विकास भारत और ईरान द्वारा कनेक्टिविटी और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है।
- चाबहार, जो ओमान की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है, ईरान का पहला गहरे पानी का बंदरगाह है जो ईरान को वैश्विक समुद्री व्यापार मार्ग मानचित्र पर लाता है।
- यह बंदरगाह पाकिस्तान के साथ ईरान की सीमा के पश्चिम में स्थित है, लगभग ग्वादर, जो पाकिस्तान में चीन द्वारा विकसित एक प्रतिस्पर्धी बंदरगाह है, सीमा के पूर्व में स्थित है।

चाबहार का भारत के लिए रणनीतिक महत्व क्या है?

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- जब चाबहार के लिए पहले समझौते पर 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हस्ताक्षर किए थे, तो इस योजना के तीन मुख्य रणनीतिक उद्देश्य थे:
  - भारत का पहला अपतटीय बंदरगाह बनाना और खाड़ी में भारतीय बुनियादी ढांचे की शक्ति को प्रदर्शित करना;
  - पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण संबंधों को देखते हुए,उससे होकर होने वाले व्यापार को दरकिनार करना और दीर्घकालिक, टिकाऊ समुद्री व्यापार मार्ग का निर्माण करना; और
  - अफगानिस्तान के लिए एक वैकल्पिक भूमि मार्ग खोजना।
- पिछले कुछ वर्षों में, चाबहार का चौथा रणनीतिक उद्देश्य सामने आया है, चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के तहत स्थापित चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) के विकल्प के रूप में कार्य करना।

चाबहार का ईरान के लिए रणनीतिक महत्व:

- चाबहार बंदरगाह ईरान के लिए रणनीतिक महत्व रखता है। यह संभावित रूप से ईरान को पश्चिमी प्रतिबंधों के प्रभाव से बचाने में मदद कर सकता है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- यह बंदरगाह प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) का भी हिस्सा है, जो एक बहु-मॉडल परिवहन परियोजना है जो हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को ईरान के माध्यम से कैस्पियन सागर और रूस में सेंट पीटर्सबर्ग के माध्यम से उत्तरी यूरोप तक जोड़ती है।

चाबहार बंदरगाह परियोजना को लेकर आगे का रास्ता:

- चाबहार परियोजना अपनी चुनौतियों के साथ जुड़ी है, मुख्य रूप से अमेरिकी प्रतिबंधों और दबावों के प्रति संवेदनशीलता, इसराइल –ईरान संघर्ष, अफगानिस्तान में अस्थिरता और निरंतर अनिश्चितताएं, और चीन के BRI के साथ प्रतिस्पर्धा।
- हालांकि, सक्रिय और दूरदर्शी कूटनीति और परियोजना के कुशल कार्यान्वयन और संचालन के माध्यम से, ईरान और भारत इन चुनौतियों पर काबू पा सकते हैं और चाबहार परियोजना को एक व्यवहार्य पारगमन केंद्र और लिंक के रूप में बनाए रखने में सक्षम हो सकते हैं।

INSTC के संदर्भ में चाबहार बंदरगाह का महत्व:

- चाबहार बंदरगाह की उपयोगिता और महत्व 'अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC)' से जुड़ा है, जो ईरान और कैस्पियन सागर के माध्यम से

शिपिंग, सड़क और रेल सहित 72,00 किलोमीटर लंबे मल्टी-मॉडल परिवहन गलियारे के माध्यम से भारतीय बंदरगाहों को रूसी संघ से जोड़ता है।

- यह कनेक्टिविटी परियोजना मूल रूप से 2000 में भारत, ईरान और रूस द्वारा कल्पना की गई थी, जिसे आने में काफी समय हो गया है।

- उल्लेखनीय है कि INSTC भारत को रूस से जोड़ने वाला सबसे छोटा व्यापार मार्ग है। 2014 के एक अध्ययन में पाया गया कि INSTC, पारंपरिक स्वेज मार्ग की तुलना में 30 प्रतिशत सस्ता और 40 प्रतिशत छोटा रास्ता है, जिससे यूरोप जाने वाले शिपमेंट के लिए पारगमन समय पारंपरिक 45-60 दिन से घटकर औसतन 23 दिन हो गया है।

भारत में गरीबी अनुमान ऐतिहासिक रूप से पांच प्रतिशत से नीचे पहुंचा:

चर्चा में क्यों है?

- SBI रिसर्च द्वारा 3 जनवरी को जारी एक अध्ययन के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में तेजी से कमी आई है, क्योंकि ग्रामीण गरीबी अनुपात पहली बार 5 प्रतिशत से नीचे गिरकर वित्त वर्ष 2022-23 में 7.2 प्रतिशत से 4.86 प्रतिशत हो गया है। इसकी तुलना में, इसी अवधि के दौरान शहरी क्षेत्रों में गरीबी अनुपात 4.6 प्रतिशत से घटकर 4.09 प्रतिशत हो गया।
- इस रिपोर्ट में ग्रामीण गरीबी में तेज कमी का श्रेय निम्न आय वर्ग के बीच खपत वृद्धि को दिया गया है, जिसे मजबूत सरकारी समर्थन से बल मिला है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

ग्रामीण गरीबी अनुपात में कमी का क्या कारण है?

ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत भौतिक अवसंरचना:

- उल्लेखनीय है कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के नवीनतम घरेलू उपभोग सर्वेक्षण (HCES) के परिणामों पर आधारित इस अध्ययन में कहा गया है कि उन्नत भौतिक अवसंरचना ग्रामीण गतिशीलता में एक नई कहानी लिख रही है।
- क्योंकि यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच तेजी से घटते क्षैतिज आय अंतर और ग्रामीण आय वर्गों के भीतर ऊर्ध्वाधर आय अंतर के कारणों में से एक है।

ग्रामीण क्षेत्र में सरकार की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन:

- इसके अलावा, इस रिपोर्ट में ग्रामीण-शहरी अंतर में कमी का कारण ग्रामीण क्षेत्र में सरकार की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन बताया गया है।
- ग्रामीण प्रति व्यक्ति मासिक व्यय (MPCE) का लगभग 30 प्रतिशत ग्रामीण पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्जात कारकों द्वारा समझाया गया है। इस तरह के अंतर्जात कारक ज्यादातर DBT हस्तांतरण, ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण, किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण आजीविका में उल्लेखनीय सुधार के मामले में सरकार द्वारा की गई पहलों के कारण हैं।

रिपोर्ट में तेंदुलकर समिति के गरीबी रेखा को आधार बनाया गया:

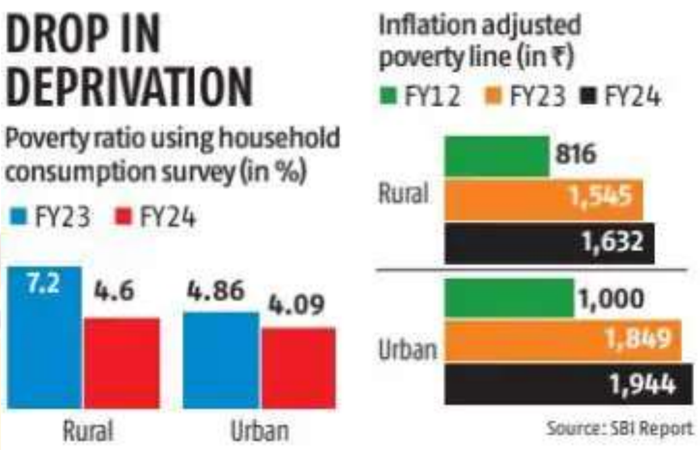

- उल्लेखनीय है कि SBI रिपोर्ट ने दशकीय मुद्रास्फीति और सुरेश तेंदुलकर द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा में आरोपण कारक को समायोजित करते हुए, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1,632 रुपये प्रति माह और शहरी क्षेत्रों के लिए 1,944 रुपये की नई गरीबी रेखा का अनुमान लगाया है।
- उल्लेखनीय है कि तेंदुलकर समिति के अनुसार, 2011-12 में भारत की कुल आबादी के 21.9 % लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करते थे।
- तेंदुलकर समिति ने अपनी रिपोर्ट में शहरी क्षेत्र में रह रहे परिवारों के संदर्भ में गरीबी रेखा को 1000 रुपए (33 रुपए प्रतिदिन) और ग्रामीण परिवारों के लिये इसे 816 रुपए (27 रुपए प्रतिदिन) निर्धारित किया था।

SBI रिसर्च रिपोर्ट की आलोचना:

- हालांकि, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के प्रोफेसर आर रामकुमार का कहना है कि SBI रिपोर्ट 2022-23 और 2023-24 के लिए गरीबी रेखा बनाने के

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

लिए तेंदुलकर समिति की गरीबी रेखा को मुद्रास्फीति के साथ अपडेट करके एक दोषपूर्ण गरीबी रेखा का उपयोग किया है।

- सबसे पहले, तेंदुलकर समिति की गरीबी रेखा गरीबी रेखा नहीं है, बल्कि सिर्फ एक "हताशा रेखा" है और पिछली सरकार को सी रंगराजन समिति का गठन करना पड़ा था। साथ ही, यह की रिपोर्ट गरीबी रेखा को अपडेट करने के लिए एक ऐसी विधि का उपयोग करती है जो परिवारों की खपत टोकरी में बदलावों को ध्यान में नहीं रखती है। ऐसे आश्चर्य की बात नहीं है कि वे गरीबी का बहुत कम स्तर प्राप्त करते हैं।
- इसके अलावा SBI रिपोर्ट NSS के क्रमिक दौर के सर्वेक्षण में पद्धतिगत बदलावों की भी ध्यान नहीं रखती है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

जॉर्ज सोरोस को दिया गया अमेरिका का 'प्रेसिडेंशियल मेडल' क्या है?

चर्चा में क्यों है?

- अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने 5 जनवरी को व्हाइट हाउस में आयोजित एक समारोह में राजनीति, मनोरंजन, खेल और अन्य क्षेत्रों में 19 सार्वजनिक हस्तियों के योगदान को सम्मानित किया और उन्हें 'प्रेसिडेंशियल मेडल' से सम्मानित किया।
- उल्लेखनीय है कि सम्मानित होने वालों में हिलेरी क्लिंटन, जॉर्ज सोरोस और रॉबर्ट एफ केनेडी (मरणोपरांत) शामिल हैं। अन्य लोगों में अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी और अभिनेता डेनजेल वाशिंगटन शामिल थे।

अमेरिकी 'प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम' क्या है?

- प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ़ फ़्रीडम संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसे अक्सर किसी व्यक्ति के जीवनकाल में किए गए कार्यों के लिए दिया जाता है।

- नवंबर 2024 की कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट कहती है कि इसे राष्ट्रपति हैरी एस. ट्रूमैन (1945 से 1953) ने 1945 में शुरू किया था। बाद में 1963 में राष्ट्रपति जॉन एफ़ कैनेडी द्वारा इसका नाम बदला गया था।
- इस पदक में लाल पंचकोण के ऊपर एक सफेद सितारा है, जिसके चारों ओर पाँच सुनहरे ईगल हैं। इसके केन्द्र में 13 सुनहरे सितारों वाला एक नीला वृत्त है।

- यह राष्ट्रपति को किसी भी व्यक्ति को मान्यता देने की अनुमति देता है जिसने (1) संयुक्त राज्य अमेरिका की सुरक्षा या राष्ट्रीय हितों, या (2) विश्व शांति, या (3) सांस्कृतिक या अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक या निजी प्रयासों में विशेष रूप से सराहनीय योगदान दिया हो।

प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ़ फ़्रीडम का चयन कैसे किया जाता है?

- प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ़्रीडम के प्राप्तकर्ताओं को नामांकित करने और चुनने के लिए कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं है। 13 मार्च, 1970 के कार्यकारी आदेश के तहत राष्ट्रपति द्वारा अपनी पहल पर चुने गए किसी भी व्यक्ति को पदक प्रदान करने की

पूरी छूट है। कभी-कभी, अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों ने पुरस्कार के लिए सिफारिश के पत्र भेजे हैं।

- पुरस्कार विजेताओं का चयन अक्सर अमेरिकी राष्ट्रपति के राजनीतिक और व्यक्तिगत हितों को दर्शाता है। जो बिडेन के मामले में, उनकी सूची को वर्तमान में देश की राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थापना के लिए समर्थन के रूप में व्याख्या किया गया है, कुछ ऐसा जिसके खिलाफ आने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अक्सर विरोध करते हैं।

हमेशा चर्चा में रहने वाला जॉर्ज सोरोस वास्तव में कौन हैं?

- जॉर्ज सोरोस एक हेज फंड मैनेजर से परोपकारी व्यक्ति बना है। उनका जन्म 1930 में हंगरी के बुडापेस्ट में यहूदी माता-पिता के घर हुआ था। हंगरी में कम्युनिस्टों के सत्ता में आने के बाद, सोरोस 1947 में लंदन चला गया और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की। 1956 में, वह अमेरिका चला गया और 1973 में, अपना खुद का हेज फंड लॉन्च किया और अपने सफल मुद्रा व्यापार, विशेष रूप से 1992 में ब्रिटिश पाउंड के खिलाफ अपने दांव के लिए जाना गया। आलोचकों ने कहा है

कि सोरोस ने पाउंड की शॉर्टिंग के साथ बैंक ऑफ इंग्लैंड को "तोड़" दिया। दिसंबर 2022 में, एक फ्रांसीसी अदालत ने उसे इनसाइडर ट्रेडिंग का दोषी ठहराया।

- जॉर्ज सोरोस की कुल संपत्ति 8.5 अरब डॉलर है, और इस महत्वपूर्ण वित्तीय ताकत का लाभ उठाकर उसने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन बनाया जो अब 100 से अधिक देशों में उपस्थिति है।
- जॉर्ज सोरोस को अमेरिका में एक "डेमोक्रेटिक (पार्टी) मेगा डोनर" के रूप में पहचाना जाता है, और उसने बराक ओबामा, हिलेरी क्लिंटन और जो बिडेन के राष्ट्रपति अभियानों का समर्थन और वित्तपोषण किया है। सोरोस पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का एक शक्तिशाली आलोचक हैं।

जॉर्ज सोरोस वर्तमान मोदी सरकार का कट्टर विरोधी:

- जॉर्ज सोरोस मोदी सरकार की कट्टर आलोचक रहा है। जनवरी 2020 में दावोस में, उसने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम और कश्मीर में 2019 के संवैधानिक परिवर्तनों का उल्लेख किया, और इन कार्यों को खुले समाजों के लिए "सबसे बड़ा और सबसे भयावह झटका" करार दिया। उसने कहा कि "लोकतांत्रिक रूप से चुने गए नरेंद्र मोदी एक हिंदू राष्ट्रवादी राज्य बना रहे हैं, कश्मीर, एक अर्ध-स्वायत्त

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

मुस्लिम क्षेत्र पर दंडात्मक उपाय लागू कर रहे हैं, और लाखों मुसलमानों को उनकी नागरिकता से वंचित करने की धमकी दे रहे हैं"।

- सोरोस ने म्यूनिख में मोदी सरकार को हटाने के लिए अपने इरादे की भी घोषणा की थी।